देस राज बंसल (मृतक) बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (जी. आर. मजीठिया, न्यायमूर्ति)

वी. रामास्वामी, सी.जे. और जी.आर. मजीठिया न्यायमूर्ति के समक्ष

देस राज बंसल (मृतक),-अपीलकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-प्रतिवादी।

1987 का पत्र पेटेंट अपील संख्या 179।

1 सितम्बर 1988.

पंजाब प्री-एम्पशन अधिनियम (1913 का 1)-1944 के पंजाब एक्ट नंबर 1 द्वारा संशोधित धाराएँ. 8(2) और 21-ए-घर की बिक्री-परंपरागत अधिकार के आधार पर प्री-एम्प्शन के लिए किरायेदार का मुकदमा-मुकदमे के लंबित रहने के दौरान धारा 8(2) के तहत अधिसूचना द्वारा किरायेदार के प्री-एम्प्शन के अधिकार को पूर्वव्यापी प्रभाव से छीन लिया गया-अधिसूचना का प्रभाव प्री-एम्प्शन सूट पर - क्या प्री-एम्प्शन के अधिकार की हानि होती है - सूट क्या खारिज किया जा सकता है - पूर्वव्यापी कार्रवाई - क्या अनुमति है। माना गया कि पंजाब प्री-एम्प्शन एक्ट, 1913 की धारा 21-ए को जोड़ने से विधानमंडल का स्पष्ट इरादा था कि मुकदमे की स्थापना के बाद विक्रेता की स्थिति में स्वैच्छिक सुधार को मान्यता न दी जाए, सिवाय इसके कि ऐसा सुधार विरासत के परिणामस्वरूप हुआ हो। या उत्तराधिकार.

. (पैरा 7)

माना गया कि अधिनियम की धारा 21-ए में उल्लिखित सुधार पार्टियों के कृत्यों के लिए संदर्भित है, न कि शक्तियों के वैधानिक प्रयोग के लिए। यह धारा विशेष रूप से विरासत या उत्तराधिकार द्वारा विक्रेता की स्थिति में सुधार को बचाती है, लेकिन मुकदमा शुरू होने के बाद संपत्ति में अधिकार के स्वैच्छिक अधिग्रहण के माध्यम से विक्रेता की स्थिति में किया गया कोई भी सुधार प्रभावी नहीं होगा। मुकदमे में प्री-एम्प्टर का अधिकार।

(पैरा-8)

माना गया, अधिनियम की धारा 8 उन बिक्री के संबंध में अधिसूचना की घोषणा पर विचार करती है जो पहले ही पूरी हो चुकी हैं। एक बार शक्ति का प्रयोग हो जाने के बाद, परिणामी प्रभाव यह होता है कि प्री-एम्प्शन का मुकदमा आगे नहीं बढ़ सकता है जिसके संबंध में अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (2) के तहत एक अधिसूचना जारी की गई है। प्री-एम्प्शन के सामान्य कानून के तहत प्री-एम्प्शनर्स को बिक्री की तारीख पर प्री-एम्प्शन का बेहतर अधिकार जारी रखना चाहिए और डिक्री की तारीख तक अधिकार जारी रखना चाहिए। यदि वह डिक्री पारित होने से पहले वह अधिकार खो देता है, तो प्री-एम्प्शन द्वारा कब्जे की डिक्री नहीं दी जा सकती, भले ही मुकदमे की तारीख पर उसके पास ऐसा अधिकार हो। एक बार अधिसूचना जारी हो जाने के बाद, इसका परिणाम यह होता है कि प्री-एम्प्शन का मुकदमा, भले ही दायर किया गया हो, कानून के संचालन के कारण डिक्री नहीं किया जा सकता है। पूर्वव्यापी प्रभाव वाली अधिसूचना अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) के दायरे से बाहर नहीं है।

(पैरा 16)

माननीय श्री न्यायमूर्ति गोकल चंद मितल द्वारा 1980 की सिविल रिट याचिका संख्या 3071 में पारित निर्णय दिनांक 11 मार्च, 1987 के खिलाफ पत्र पेटेंट अपील के खंड एक्स के तहत पत्र पेटेंट अपील।

अपीलकर्ताओं की ओर से प्रदीप गुप्ता, अधिवक्ता।

एन.एस.पवार, सीनियर डी.ए.जी. (हरियाणा.राज्य के लिए)

प्रतिवादी 2 के लिए वी.के. बाली, वरिष्ठ अधिवक्ता (श्री रणजीत शर्मा, उनके साथ वकील)।

निर्णय

जी आर मजीठिया, न्यायमूर्ति

(1) यह अपील विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत उन्होंने अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें 22 मई, 1980 की अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। पंजाब प्री-एम्पशन की धारा 8 की उप-धारा (2) के तहत जारी किया गया राज्य द्वारा अधिनियम, 1913 (संक्षेप में, "अधिनियम" के रूप में संदर्भित)। हरियाणा में इस आशय का कि मकान संख्या ए.एम.सी. की बिक्री के संबंध में पूर्व-खाली का कोई अधिकार मौजूद नहीं होगा। 1385-86, ब्लॉक नंबर 4, दुनी चंद रोड, नई बस्ती, अंबाला शहर, सर्वश्री कुलदीप सिंह, सेवा सिंह, अजीत सिंह और गुरमुख सिंह द्वारा 14 जून को निष्पादित चार बिक्री कार्यों के माध्यम से उपरोक्त संपत्ति के संयुक्त मालिक हैं। 17 जून और 22 जून, 1977 को, कॉलेज भवन के विस्तार के उद्देश्य से, उक्त कॉलेज के प्रिंसिपल श्री प्रेम बाल खेड़ा के माध्यम से देव समाज कॉलेज फॉर गर्ल्स (लाहौर), अंबाला शहर के पक्ष में। इस मामले का मैट्रिक्स इस प्रकार है:- मकान नंबर 1385-86, ब्लॉक नंबर 4, दुनी चंद रोड, नई बस्ती, अंबाला शहर, चार भाइयों के स्वामित्व में था और

इसके एक अलग हिस्से पर बुध राम, देस राज और बिंद्राभान ने किरायेदारों के रूप में कब्जा कर लिया था। मालिकों ने चार विक्रय पत्रों के माध्यम से पूरा घर जून, 1977 में देव समाज कॉलेज फॉर गर्ल्स (लाहौर), अंबाला शहर को बेच दिया। बुध राम और देस राज ने इस आधार पर बिक्री को रोकने के लिए अलग-अलग मुकदमे दायर किए कि वहां एक प्रथा थी। अंबाला शहर में और विशेष रूप से उस इलाके/उपमंडल में प्रचलित प्री-एम्प्शन जहां घर स्थित था, जिसके तहत एक किरायेदार को बेची गई संपत्ति या उसके हिस्से के संबंध में प्री-एम्प्शन का अधिकार था। सूट का परीक्षण कॉलेज द्वारा किया गया। मुकदमों के लंबित रहने के दौरान, अधिनियम की धारा 8(2) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा सरकार द्वारा 22 मई, 1980 को एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें घोषणा की गई थी कि प्री-एम्प्शन का कोई अधिकार मौजूद नहीं होगा। घर की बिक्री का सम्मान.

(2) देस राज ने सी.डब्ल्यू.पी. दायर की। क्रमांक 3071/1980 को इस न्यायालय में उस अधिसूचना को चुनौती देने के लिए, जिसे 3 सितंबर, 1980 को खारिज कर दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय में अपील पर, सर्वोच्च न्यायालय के 5 अप्रैल, 1983 के एक आदेश द्वारा, इस का आदेश अदालत को अलग रखा गया और आदेश दिया गया कि रिट याचिका का निपटारा किया जाए गुण.

(3) बुध राम किरायेदार सीधे सुप्रीम कोर्ट चले गए भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उन्हें उच्च न्यायालय जाने का निर्देश दिया गया। उन्होंने सी.डब्ल्यू.पी. के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। क्रमांक 995/1983 जिसे सी.डब्ल्यू.पी. में पारित पूर्व आदेश के आलोक में 31 मार्च 1987 को खारिज कर दिया गया था। 1980 का क्रमांक 3071। उन्होंने उस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी और 8 अगस्त, 1983 के एक आदेश द्वारा मामले को गुण-दोष के आधार पर निर्णय के लिए इस न्यायालय में भेज दिया गया। इन दोनों सिविल रिट याचिकाओं का निपटारा एक ही निर्णय द्वारा कर दिया गया

(4) विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष, याचिकाकर्ता ने इस आधार पर अधिसूचना पर आपत्ति जताई कि यह कानूनी दुर्भावना से ग्रस्त है। अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया जा सकता क्योंकि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 38 और 39 में निहित राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के विपरीत है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने पाया कि अधिसूचना किसी भी कानूनी दुर्भावना से ग्रस्त नहीं थी, और अधिनियम की धारा 8 में परिकल्पना की गई है कि अधिसूचना उस बिक्री के संबंध में जारी की जा सकती है जो पहले ही हो चुकी है। संविधान के अनुच्छेद 38 और 39 में निहित निदेशक सिद्धांतों के उल्लंघन के संबंध में विवाद को खारिज कर दिया गया। इस फैसले से व्यथित अपीलकर्ता अपील में आये हैं।

(5) अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने न केवल एकल न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुतीकरण दोहराया, बल्कि यह भी आग्रह किया कि अधिनियम की धारा 21-ए के आधार पर, मुकदमा शुरू होने के बाद विक्रेता की स्थिति में कोई भी सुधार हो। प्री-एम्प्शन, प्री-एम्प्शन के मुकदमे में प्री-एम्प्शन के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा। उन्होंने आग्रह किया कि मुकदमा दायर करने के बाद, अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (2) के तहत अधिसूचना जारी की गई, जिसके तहत यह घोषित किया गया कि बिक्री के संबंध में प्री-एम्प्शन का कोई

अधिकार मौजूद नहीं होगा। यह विक्रेता की स्थिति में सुधार के बराबर है और अधिनियम की धारा 21-ए से प्रभावित हुआ है।

(6) अंतिम प्रस्तुतिकरण पूरी तरह से कानून का प्रश्न है, हालांकि विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष नहीं उठाया गया, हमने वकील को तत्काल मामले में अधिनियम की धारा 21-ए की प्रयोज्यता पर प्रस्तुतियाँ देने की अनुमति दी। धारा 21-ए इस प्रकार है:- "विरासत या उत्तराधिकार के अलावा, प्री-एम्प्शन के लिए एक मुकदमा शुरू होने के बाद प्रतिवादी प्रतिवादी की स्थिति में किया गया कोई भी सुधार, ऐसे मुकदमे में वादी के प्री-एम्प्शन के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा।" इसमें कोई विवाद नहीं है कि किसी विशेष प्रावधान की व्याख्या करने और विधानमंडल के इरादे का अनुमान लगाने के लिए, विधेयक को विधानमंडल में प्रस्तुत किए जाने पर उसमें बताई गई वस्तुओं और कारणों का उपयोग किया जा सकता है। यह उस पृष्ठभूमि की जानकारी देता है कि यह अनुभाग क्यों पेश किया गया था।

(7) विधानमंडल अधिनियम की धारा 21-ए जोड़कर में स्वैच्छिक सुधार को मान्यता न देने का स्पष्ट इरादा है प्रतिवादी की स्थिति, मुकदमा संस्थित होने के बाद ऐसी स्थिति को छोड़कर सुधार विरासत या उत्तराधिकार के परिणामस्वरूप हुआ है।

(8) अधिनियम की धारा 21-ए में उल्लिखित सुधार पार्टियों के कृत्यों के लिए संदर्भित है न कि शक्तियों के वैधानिक प्रयोग के लिए। यह धारा विशेष रूप से विरासत या उत्तराधिकार द्वारा विक्रेता की स्थिति में सुधार को बचाती है, लेकिन मुकदमे की स्थापना के बाद, संपत्ति में अधिकार के स्वैच्छिक अधिग्रहण के माध्यम से विक्रेता की स्थिति में किया गया कोई भी सुधार प्रभावित नहीं करेगा। मुकदमे में प्री-एम्प्टर का अधिकार। 1944 के पंजाब अधिनियम संख्या 1 ने पंजाब प्री-एम्प्शन अधिनियम, 1913 में संशोधन किया। वस्तुओं और कारणों के विवरण में उल्लिखित भौतिक शब्द, इस प्रकार पढ़ें: - "21-ए को प्री-एम्प्शन मुकदमों के मामले में यथास्थिति बहाल करने के लिए पंजाब प्री-एम्प्शन एक्ट में जोड़ा जा रहा है, जहां प्रतिवादी संपत्ति के अधिकार के स्वैच्छिक अधिग्रहण के माध्यम से अपनी स्थिति में सुधार करना चाहता है। , मुकदमा संस्थित होने के बाद।"

(9) अधिनियम की धारा 21-ए गरीब सिंह बनाम हरनाम सिंह और अन्य[1] मामले में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के समक्ष विचार के लिए आई, और यह निम्नलिखित परिस्थितियों में उत्पन्न हुई: - "एक किशना के चार बेटे, अर्थात् गरीब सिंह, हरनाम सिंह, प्रताप सिंह और करतार सिंह, संयुक्त रूप से 225 कनाल 9 मरला कृषि भूमि के मालिक थे। करतार सिंह की मृत्यु हो गई, उनके बेटे हरचंद सिंह ने अपना 1/4 हिस्सा बेच दिया 15 मार्च, 1966 को एक पंजीकृत विक्रय विलेख द्वारा उनके चाचा गरीब सिंह और उनकी पत्नी गुरनाम कौर को संयुक्त भूमि दी गई। 15 मार्च, 1967 को, प्रतिवादी गरीब सिंह के एक भाई, हरनाम सिंह ने इस दलील पर पूर्व-खाली का मुकदमा दायर किया कि वह विक्रेता हरचंद सिंह के सह-हिस्सेदार और निकट

[1] 1972 पी.एल.आर. 186

संपार्श्विक भी थे। मुकदमे की सुनवाई के दौरान, 10 जून, 1968 को, गुरनाम कौर ने जमीन के अपने हिस्से का एक उपहार दिया, जिसे उन्होंने संयुक्त रूप से खरीदा था अपने पति के साथ अपने सह-प्रतिनिधि गरीब सिंह को। अपने पक्ष में इस उपहार का लाभ उठाते हुए गरीब सिंह ने अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर प्री-एम्प्शन के मुकदमे का विरोध किया कि उसके पक्ष में उपहार के परिणामस्वरूप, उसकी पत्नी (जो एक थी) अजनबी) की संपत्ति में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई है और उसका अपना अधिकार पूर्व-एम्प्टर के बराबर है, तो मुकदमा विफल हो जाना चाहिए।"

(10) निम्नलिखित प्रश्न तैयार किया गया और पूर्ण पीठ को भेजा गया:- "क्या कोई विक्रेता, जिसने कृषि भूमि या अचल संपत्ति खरीदने में किसी अजनबी को शामिल किया है, उपहार या बिक्री द्वारा अजनबी सह-विक्रेता के हित को प्राप्त करके, धारा 21 के प्रावधानों के मद्देनजर प्री-एम्प्शन के मुकदमे का सफलतापूर्वक विरोध कर सकता है- पंजाब फ्री-एम्प्शन एक्ट, 1913 का ए?"

(11) गुरदेव सिंह, जे. ने बेंच के लिए बोलते हुए निम्नानुसार कहा: "वास्तव में, पंजाब प्री-एम्प्शन एक्ट की धारा 21-ए पर उनके द्वारा रखी गई रचना उस उद्देश्य के अनुरूप है जिसके साथ यह प्रावधान 1944 के संशोधन अधिनियम संख्या 1 द्वारा पेश किया गया था। इस संशोधन द्वारा, जैसा कि भी किया गया है पहले देखा गया था, विधायिका का स्पष्ट इरादा था कि मुकदमे की स्थापना के बाद प्रतिशोधी की स्थिति में कोई स्वैच्छिक सुधार नहीं होगा, बल्कि केवल विरासत या उत्तराधिकार के परिणामस्वरूप होने वाले सुधारों को मान्यता दी जाएगी।"

(12) दूसरी अपील में, इस न्यायालय के माननीय न्यायाधीश ने माना कि गरीब सिंह द्वारा उपहार के तहत अपनी पत्नी के हिस्से का अधिग्रहण स्थिति में सुधार और धारा 21-ए के प्रावधानों के मद्देनजर है। पंजाब प्री-एम्प्शन एक्ट, गरीब सिंह को इससे लाभ नहीं मिल सका।

(13) इस प्रकार, विद्वान वकील की दलील निराधार है और खारिज करने योग्य है।

(14) विद्वान वकील ने आगे कहा कि अधिसूचना कानूनी दुर्भावना से ग्रस्त है और उन्होंने हमारा ध्यान याचिका के साथ संलग्नक पी.10 के रूप में संलग्न एक नोट की ओर आकर्षित किया जिसमें राजस्व मंत्री विभाग के प्रस्ताव से अलग थे। विभाग ने सुझाव दिया कि बिक्री को अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) के तहत छूट दी जानी चाहिए लेकिन मंत्री ने एक असंगत टिप्पणी दर्ज की। हमने मूल फाइल तलब की और वरिष्ठ उप महाधिवक्ता हरियाणा, जो राज्य की ओर से हमारे सामने पेश हुए, ने मूल फाइल पेश की। राजस्व मंत्री के विभाग में दोबारा नोटिंग के बाद मामले की जांच की गई। दोबारा जांच करने पर विभाग ने अनुशंसा की कि मामले की परिस्थितियों के आलोक में अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) के तहत छूट दी जाये। मंत्री विभाग द्वारा की गई अनुशंसा से सहमत हुए। 17 नवंबर, 1979 को इस मामले पर मुख्यमंत्री के साथ चर्चा की गई और उन्होंने निर्देश दिया कि अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) के तहत छूट दी जाए। राजस्व मंत्री ने 21 नवंबर, 1979 को मुख्यमंत्री के साथ मामले पर चर्चा की और उसके बाद बिक्री में छूट

देने का अंतिम निर्णय लिया गया। अंतिम निर्णय के बाद 22 मई, 1980 को एक अधिसूचना जारी की गई। मंत्री के नोट को जीवन पर बाद की टिप्पणियों से अलग करके नहीं पढ़ा जा सकता। मंत्री का यह नोट विद्वान वकील के लिए कोई सहायता नहीं है। अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री द्वारा लिया गया, जिससे राजस्व मंत्री श्री शेर सिंह सहमत हुए, जिन्होंने पहले अवसर पर एक अलग दृष्टिकोण रखा था। ऐसा प्रतीत होता है कि जब राजस्व मंत्री के सामने सारी सामग्री रखी गई तो उनका मन बदल गया।

(15) अधिनियम की धारा 5 और 9 विशेष रूप से कुछ पूर्व-पक्षों को पूर्वक्रय से बचाती हैं। धारा 8 को अधिनियम की योजना के आलोक में पढ़ा जाना चाहिए। यह शक्ति उस छूट से स्वतंत्र है जो अधिनियम की धारा 9 द्वारा वैधानिक रूप से निर्धारित है। अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (2) के तहत शक्तियों का प्रयोग स्पष्ट रूप से धारा 9 में निर्दिष्ट प्रकृति के लेनदेन तक सीमित नहीं है। ये वैधानिक छूट हैं। बिक्री के लेन-देन को अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) के तहत प्री-एम्प्शन से छूट दी जा सकती है। कानून में द्वेष तब माना जा सकता है जब कोई आदेश उस क़ानून के उद्देश्य और उद्देश्य के विपरीत किया जाता है जिसके तहत आदेश दिया जाता है। अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) राज्य सरकार को एक अधिसूचना द्वारा घोषित करने में सक्षम बनाती है कि किसी भी बिक्री या बिक्री के किसी भी वर्ग के संबंध में पूर्व-खाली का कोई अधिकार मौजूद नहीं होगा। हमारे सामने जो दोहराया गया है, वह सरकारी रिकॉर्ड पर उपलब्ध था और हमने पाया कि अपीलकर्ताओं द्वारा प्रतिनिधित्व के माध्यम से इसे सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और सरकार ने प्रतिनिधित्व प्राप्त होने पर मामले की जांच की और रिपोर्ट मांगी। उपायुक्त से और बाद वाले ने छूट देने की सिफारिश की। सरकार ने संपूर्ण सामग्री की गहन जांच के बाद अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करने का निर्णय लिया। क़ानून के उद्देश्य और उद्देश्य के विपरीत शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। इस प्रकार, यह कहना पूरी तरह से गलत है कि अधिसूचना कानूनी दुर्भावना से ग्रस्त होकर दूषित है। इसके अलावा, हमने पाया कि विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष जो प्रस्तुत किया गया था वह यह था कि जिस कॉलेज के लिए जमीन खरीदी गई थी उसका स्वामित्व श्री प्रेम बाल खेड़ा और संस्था के पास था। देव समाज द्वारा इसका रखरखाव नहीं किया गया। विद्वान एकल न्यायाधीश मामले पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद यह निष्कर्ष निकला कि कॉलेज का स्वामित्व और प्रबंधन देव समाज संस्था द्वारा किया जाता है और इसका स्वामित्व किसी व्यक्ति के पास नहीं है, हम इससे सहमत हैं।

(16) धारा 8 में पहले ही पूरी हो चुकी बिक्री के संबंध में एक अधिसूचना जारी करने पर विचार किया गया है। एक बार शक्ति का प्रयोग हो जाने के बाद, परिणामी प्रभाव यह होता है कि प्री-एम्प्शन का मुकदमा आगे नहीं बढ़ सकता है जिसके संबंध में अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (2) के तहत एक अधिसूचना जारी की गई है। प्री-एम्प्शन के सामान्य कानून के तहत प्री-एम्प्टर्स को प्री-एम्प्शन का श्रेष्ठ अधिकार जारी रखना चाहिए। बिक्री की तारीख पर और डिक्री की तारीख तक उस अधिकार को बरकरार रखना होगा। यदि वह डिक्री पारित होने से पहले वह अधिकार खो देता है, तो प्री-एम्प्शन द्वारा कब्जे की डिक्री नहीं दी जा सकती, भले ही मुकदमे की तारीख पर उसके पास ऐसा अधिकार हो। एक बार अधिसूचना जारी हो जाने के बाद, परिणामी प्रभाव प्री-एम्प्शन के लिए मुकदमा होता है। भले ही दायर किया गया हो. कानून लागू होने के

कारण डिक्री नहीं दी जा सकती। पूर्वव्यापी कार्रवाई वाली अधिसूचना अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) के दायरे से बाहर नहीं है। सरदारनी चानन कौर और अन्य बनाम मोहन लाल गोयला और अन्य का संदर्भ लेना उपयोगी होगा। (2) जिसमें इसे निम्नानुसार रखा गया था:-

"यह धारा बहुत स्पष्ट शब्दों में स्थानीय सरकार को किसी भी बिक्री के संबंध में यह घोषित करने का अधिकार देती है कि प्री-एम्प्शन का कोई अधिकार या केवल उसके द्वारा निर्दिष्ट सीमित अधिकार मौजूद नहीं होगा। स्थानीय सरकार को यह अधिकार दिया गया है न केवल बिक्री के किसी भी वर्ग के संबंध में, बल्कि किसी विशेष बिक्री के संबंध में भी ऐसी घोषणा करने की शक्ति है और यह स्पष्ट है कि जहां घोषणा किसी विशेष बिक्री के संबंध में की जाती है, बिक्री की घोषणा से पहले होनी चाहिए। अधिसूचना। इसलिए, अनुभाग स्पष्ट रूप से उन बिक्री के संबंध में एक अधिसूचना की घोषणा पर विचार करता है जो पहले ही पूरी हो चुकी है और तदनुसार, यह आग्रह नहीं किया जा सकता है कि पूर्वव्यापी संचालन वाली अधिसूचना अनुभाग के दायरे से बाहर है।

(17) भारत के संविधान के अनुच्छेद 38 और 39 आते हैं भाग-IV "राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत" शीर्षक के अंतर्गत। निदेशक सिद्धांतों का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है- उचित राज्य कार्रवाइयों द्वारा डोम। इसकी शायद ही कोई प्रासंगिकता रह गई है तत्काल मामले में. शीर्ष न्यायालय ने एक से अधिक बार इस पर विचार किया है। पूर्व-मुक्ति का अधिकार एक चोरी करने के समान अधिकार है। अपीलकर्ता प्रथा के आधार पर प्री-एम्प्शन के अधिकार को लागू करने की मांग कर रहे हैं। संस्थान के व्यापक हित में, सरकार ने अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग किया। अपीलकर्ताओं का कब्ज़ा तब तक बना रहेगा जब तक उन्हें क़ानूनी प्रक्रिया के तहत बेदखल नहीं कर दिया जाता।

(18) कॉलेज लाहौर में और विभाजन के बाद चलाया जा रहा था देश के सबसे पहले इसे अंबाला शहर में खोला गया। यह शहर के मध्य में है और कॉलेज से सटी जमीन खरीदने के अलावा इसमें विस्तार की कोई गुंजाइश नहीं है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस संस्था का विस्तार करने की वास्तविक आवश्यकता थी। कुछ आलोचना है कि इस संस्थान की जमीन पर कुछ दुकानें बनाई गई हैं। हो सकता है कि वित्तीय तंगी को दूर करने के लिए ऐसा किया गया हो। कॉलेज है. एक प्रमुख संस्थान और इसके नतीजे बताते हैं कि बड़ी संख्या में छात्रों ने उच्च स्थान हासिल किए और मेरिट सूची में आए। कॉलेज ने, संस्थान चलाने के लिए अपनी आय की पूर्ति के लिए, सड़क के किनारे दुकानें बनाई होंगी। यह संभव है कि यदि ऐसा नहीं किया गया होता, तो नगरपालिका समिति या इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने उस भूमि को एक वाणिज्यिक परिसर की स्थापना के लिए अधिग्रहित कर लिया होता। संभवतः इसे ध्यान में रखते हुए, संस्थान ने आय बढ़ाने और वाणिज्यिक परिसर की स्थापना के लिए नगरपालिका समिति या अन्य अधिकारियों द्वारा अधिग्रहण से बचाने के लिए दुकानें बनाईं और उन्हें किराए पर दे दिया। लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए ऐसी संस्था चलाने का उद्देश्य प्रशंसनीय है और हमें नहीं लगता कि इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता है। अपील खारिज की जाती है. हालाँकि, हम पार्टियों को उनकी लागत स्वयं वहन करने के लिए छोड़ते हैं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

तुषार शर्मा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी , कैथल, हरियाणा